(c) and (d) Government of Bihar has got Action Plan preparead through a research institution. This Action Plan was fully fiunded by Govenrment of India. The draft report was submitted to the State Govt. in July, 1995. The State Government is expected to make use of the report while formulating and implementing the housing schemes to suit their requirements out of their plan funds. No direct Central assistance is given for State plan housing schemes. Howver, HUDCO provides loan assistance for such schemes.

प्राकृतिक संसाधनों संबंधी राष्ट्रीय नीति

1437. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए सरकार ने किन-किन विशेष बातों पर बल दिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना ने माना है बुनियादी संसाधन निधियां अर्थात् ऊर्जा स्रोत, भूमि, जल और अन्य अनिवार्य खनिज, पर्यावरण और पारिस्थितिकी आदि विकास और तुलनात्मक लाभ के लिये क्षमता निर्धारण में महत्वपूर्ण तत्व हैं। विकास परिदृश्य से संबंधित आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों में प्राकृतिक संसाधनों पर सामान्य ब्यौरे प्रस्तुत किये गये थे।

यह अनिवार्य है कि जो प्रक्रियायें ऊर्जा के उपयोग की किफायत करती है और कच्ची सामग्री का बर्बादी को बचाती है उन्हें अपनाया जाना चाहिए। योजना में दर्शाई गई और नवीकरण योग्य संसाधन कार्य नीतियों का कार्यान्वयन अपेक्षित है।

प्रोयोगिकी और प्रक्रियायों में परिवर्तन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रकों में ऊर्जा की तेजी को घटाने के लिए उपाय शुरु किए जाने होंगे। अंतर ऊर्जा और बाह्य ऊर्जा एवजियों को इष्टतम बनाना होगा। ऊर्जा के नवीकरण योग्य स्रोतों के उपयोग को अधिकतम करने की ओर मुख्य बल देना होगा। उत्पादन के लिए ऊर्जा खपत कम करने हेतु कार्य कौशल, संरक्षण और मांग प्रबन्धन पर सबसे अधिक जोर देना होगा।

जल उपयोग के क्षेत्र में जल प्रबन्धन को कुशलता में सुधार और सतही और भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग, पर्याप्त कायम रखने योग्य अनुरक्षण और किसानों की भागीदारी द्वारा की गई सिंचाई के माध्यम से उपयोग किये गये जल की उत्पादकता को बढ़ाना अनिवार्य है।

खनिज संसाधन नवीकरण योग्य न होने के कारण, खनिज भण्डारों की खोज और अन्वेक्षण और वैज्ञानिक रूप से योजित मांग प्रबनधन दूसरे प्रतिस्थापनों के उपयोग द्वारा इनके लिए अधिक उत्पसाहजनक और सतत् प्रयासों की आवश्यकता होती है।

हिमालय क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज

1438. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने हिमालय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के राजौरी और सरोईसर में, हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी और सरकाघाट में तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल में पेट्रोल की खोज का कार्य कई वर्ष पूर्व आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें से प्रत्येक स्थान पर खोज कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) आज तक प्रत्येक स्थान पर वर्ष-वार कितनी-कितनी राशि खर्च की गई और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भावी योजनाएं क्या-क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू): (क) और (ख) जी, हां। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में ओ एन जी सी द्वारा किए गए अन्वेषण कार्य का ब्यौरा निम्नवत है:—

जम्मू और कश्मीर में राजौरी और सुरूईसार क्षेत्रों में अन्वेषण

ओ एन जी सी 1957 से जम्मू और कश्मीर में तेल और गैस का अन्वेषण कर रही है। तृतीयक तराई क्षेत्र में भूगर्भीय, गुरूत्व चुम्बकीय और पारम्परिक भूकम्पीय सर्वेक्षणों सहित भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। ये सर्वेक्षण कश्मीर घाटी में भी किए गए। भूकंपीय सर्वेक्षण मार्च, 1996 से राजौरी में शुरू किए गए उप-सतही संरचनात्मक आकृति चित्रित करने और संभावनाओं का

पता लगाने के लिए ये सर्वेक्षण जारी हैं। अनुकूल आसारों के आधार पर नौवीं योजना में एक अन्वेषक कूप का वेधन शुरू किए जाने की संभावना है। जहां तक सुरूईसार का संबंध है, 1970 में एक अन्वेषक कूप का वेधन किया गया। तदुपरांत सुरूईसर-मनसब क्षेत्र में आधुनिक सी डी पी भूकंपीय सर्वेक्षण भी किए गए। आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण के पश्चात् अस्सी के दशक के उत्तरवर्ती भाग में एक और अन्वेषक कूप का असफल वेधन किया गया। हाल में जम्मू-कश्मीर के रामनगर क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण जारी हैं।

हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी और सरकाघाट क्षेत्र में अन्वेषण:

हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी क्षेत्र में ओ एन जी सी द्वारा अपने आरंभ के दिनों से हाईड्रोकार्बनों का अन्वेषण शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश के ताराई क्षेत्र का भूवैज्ञानिक नक्शा तैयार किया गया है। बेसिन समाकृति को चित्रित करने के लिए 1965 में राज्य में गुरूत्व-चुम्बकीय सर्वेक्षण आरंभ किए गए। इनमें से अधिकांश क्षेत्र गुरूत्व चुम्बकीय सर्वेक्षणों में शामिल कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भूकंपीय सर्वेक्षण 1970 में आरंभ किए गए और वे अभी भी जारी हैं। इनमें से अधिकांश सर्वेक्षण ज्वालामुखी, सरकाघाट, पारोर और सुन्दर नगर क्षेत्रों में किए गए। इन सर्वेक्षणों से ज्वालामुखी-बल्ह क्षेत्र में उप सतही संरचनात्मक समाकृति तैयार करने में सहायता मिली है जिसके आधार पर कुछ अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया गया। ज्वालामुखी-बल्ह क्षेत्र में 2-3 कूपों में गैर-वाणिज्यिक/थोड़ी सी गैस के संकेत के अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य में किन्हीं वाणिज्यिक हाईड्रोकार्बनों की खोज नहीं हो पाई है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश) में अन्वेषण:

इस क्षेत्र में ओ एन जी सी द्वारा हरिद्वार-कोट द्वार, राजपुर-तलनाड़ी, उदमसिंह नगर-नैनीताल तथा उत्तरकाशी और देहरादून जिलों के भागों जैसे स्थानों में भूवैज्ञानिक चंक्रमों/मानचित्रणों के रूप में अन्वेषणात्मक प्रयास किए गए। विकास नगर और देहरादून के क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षण किए गए हैं।

उत्तरांचल के अधिकांश क्षेत्र में रूपांतरकारी भूभाग शामिल है, जो तेल और गैस अन्वेषण के लिए कोई महत्व नहीं रखता।

(ग) ओ एन जी सी में सर्वेक्षण व्यय का रिकार्ड क्षेत्रवार रखा जाता है। ओ एन जी सी के उत्तरी क्षेत्र कार्यक्रम केन्द्र (एन आर बी सी) में सर्वेक्षणों पर व्यय, जिनमें पिछले 5 वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में प्रचालन शामिल हैं, निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

1991-92	13.07
1992-93	14.07
1993-94 (31.1.94 को समाप्त 10 माह)	12.96
1994-95 (31.3.95 को समाप्त 14 माह)	22.11
1995-96	18.35

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राज्यों और निकटवर्ती राज्यों में उत्तरी क्षेत्र कार्यक्रम केन्द्र के संबंध में सर्वेक्षणों पर 31.3.1996 तक व्यय (मूल्य ह्रास सहित) 175.76 करोड़ रुपये है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्यों में अन्वेषणात्मक वेधन पर किया गया व्यय निम्नवत् है:

	जम्मू-कश्मीर	हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश
1991-92	—	13—58	13.05
1992-93	—	7—63	11.56
1993-94 (10 महीने)	—	0—66	—
1994-95 (14 महीने)	—	—	—
1995-96	—	—	—

(उपर्युक्त आंकड़ों में मूल्य ह्रास भी शामिल है)

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संबंध में 31.3.1996 तक अन्वेषणात्मक वेधन पर खर्च की गई धनराशि नीचे दिए अनुसार है:

	(करोड़ रुपये)
जम्मू-कश्मीर	56.03
हिमाचल प्रदेश	104.54
उत्तर प्रदेश	52.36

(घ) जम्मू-कश्मीर के पूंछ-राजौरी-कालाकोट क्षेत्र में कुल 300 जी एल के, 2डी भूकंपीय आंकड़े प्राप्त करने की योजना है। बिलासपुर के दक्षिण, स्तरकाघाट-सुन्दर नगर के दक्षिण-पूर्व के क्षेत्रों में से प्राप्त आंकड़ों का निर्वचन इनको संसाधित किए जाने के बाद किया जाएगा। इस निर्वाचन के आधार पर इस क्षेत्र के लिए अन्वेषण की अगली योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में किसी कार्य पर विचार नहीं किया गया है।

Fall in Power Production capacity and profits of PSUs

1439. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have recently undertaken any review of some PSUs under Ministry of Power wherein production capacity and profits have been falling for the past few years;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any of such loss making PSUs have expressed the desire to adopt their own policies to make them profitable;

(d) if so, whether Government favour the policy of deregulation, delicencing of industry, removal of import controls and capital issue control and streamlining of the regulatory processes; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (c) There are no loss-making PSUs under the Ministry of Power, warranting any special review in this regard.

(d) to (e) Do not arise.

Rail Based Mass Rapid Transport System Projects for Delhi

1440. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have since cleared the project for rail-based Mass Rapid Transport System (MRTS) for Delhi;

(b) if so, the details of the project, indicating the cost and time-frame for its implementation; and

(c) the steps taken and being taken to implement the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) Yes, Sir.

(b) The first phase of the proposed